कार्यक्रम शामिल किये हैं और ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं जो आरम्भ कर दी गयी हैं तथा पूरी होने वाली है ; और

(ख) कहलगांव में बिजली का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बिहार में विद्युत की उपलब्धता में बढ़ौतरी करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिनसे 7वीं तथा 8वीं योजना की बाकी अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होंगे :—

स्कीम का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	के दौरान लाभ (मेगावाट)	
		1987-90	8वीं योजना
1. उत्तरी कोयल जल विद्युत परियोजना	24.0	24.0	–
2. सोन पश्चिमी सम्पर्क जल विद्युत परियोजना	6.6	6.6	–
3. सोन पूर्वी सम्पर्क जल-विद्युत परियोजना	3.3	3.3	–
4. पूर्वी गंडक नहर (जल विद्युत)	15.0	15.0	-
5. चंदेल जल-विद्युत परियोजना	8.0	–	8.0
6. तेनघाट ताप विद्युत परियोजना	420.0	210.0	210.0
जोड़ :	476.9	258.9	218.0

इसके अतिरिक्त, पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं और चूखा परियोजना से भी राज्य को इसका हिस्सा प्राप्त होगा। पतरातू, बरौनी और कारवी धैया ताप-विद्युत केन्द्रों में 67.26 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 25.81 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएंगे।

(ख) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक के पहले यूनिट को 1991 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है ?

उत्तर प्रदेश की बिजली सम्बन्धी मांग

2371. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस वर्ष के सूखे की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की मांग को किस प्रकार पूरा करनेमें का विचार रखती है ;

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली की आवश्यकता है और यहां बिजली की मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है ; और

(ग) कृषि, औद्योगिक और गैर-सरकारी क्षेत्र को अलग-अलग बिजली सप्लाई में कितने प्रतिशत कटौती वहन करनी पड़ेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) इस वर्ष सूखे की स्थिति के दौरान जहां तक संभव हो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से विभिन्न उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया था। इन उपायों में ये शामिल हैं, तापविद्युत केन्द्रों से विद्युत का अधिक उत्पादन करना, भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को

क्रियान्वित करना। जिस सीमा तक संभव होता है उत्तर प्रदेश को सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के अनाबंटित विद्युत के हिस्से में से भी इसके हिस्से से भी अधिक विद्युत सप्लाई की जाती है।

(ख) अक्तूबर, 1987 के दौरान राज्य की ऊर्जा की आवश्यकता 2020 मिलियन यूनिट थी जबकि इसकी तुलना में 1658 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध थी। यह 362 मिलियन यूनिट (17.9 प्रतिशत) विद्युत की कमी का सूचक है।

(ग) राज्य में विद्युत की मांग और उपलब्धता संबंधी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करने का निर्णय लिया जाता है। विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। राज्य से अनुरोध किया गया है कि कृषि क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इस समय उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन 10 से 12 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है।

Monitoring of Bulk Drug Production

2372. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government monitors the production of 87 bulk drugs; and

(b) if so, the names of those drugs along with production of each during last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Details are available in the performance Budget of this Ministry, Copies of which are available in the Parliament Library.

Price Control of Oxyfederine HCL

2373. SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 858 given in the Rajya Sabha on the 16th November, 1987 and state whether Oxyfederine Hcl would be brought under price control as Ildaman the major selling brand based on this drug is the monopoly production and is being imported in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): The term of Kelkar Committee set up for indentification of Category II drugs was extended in August, 1987 for a period of six months to perform the functions of reviewing any representations received by the Government regarding any discrepancies, anomalies, etc. in the list of new DPCO, 1987 and give its recommendations to the Government on the same. This drug also is being referred to the Committee.

Exclusion of Certain Drugs from Price Control

2374. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one of the criteria laid down by the Kelkar Committee for decontrol of drug prices, is competitive structure;

(b) whether structure is having more then five bluk drug producers and ten formulators;

(c) if so, whether it is a fact certain drugs have not been excluded from control despite fulfilling this criteria; and

(d) if so, what are the names of those drugs and the reasons for inclusion of each under price control?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) to (d) The criteria adopted by the Kelkar Committee for identifying the drugs to be included